(घ) चूंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित राशि के बारे में बताना अभी समयपूर्व होगा। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव गैर-योजनागत निधियों में से किया जाता है और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर वर्ष दर वर्ष धनराशि आवंटित की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक आवासों, होटलों और यात्री-निवासों का निर्माण

250 **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश में जिला-वार बनाए गए पर्यटक आवासों, होटलों, और यात्री-निवासों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) ये होटल आदि किन-किन स्थानों पर हैं और इसके लिए उन्हें कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) इस समय केंद्रीय सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्ताव हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (**श्री माधवराव सिंधिया**) : (क) और (ख) केंद्रीय पर्यटन विभाग ने गत पांच वर्षों के दौरान पर्यटक होटलों या होस्टलों का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता नहीं दी है । तथापि, इलाहाबाद में एक यात्री निवास तथा माल्वीपुर में एक अन्य यात्री निवास के लिए वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि क्रमशः 29.42 लाख और 40.20 लाख रुपए) दी गई है ।

(ग) और (घ) 1991–92 के दौरान , अयोध्या और चित्रकूट में दो यात्री निवासों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुसूचों सहित विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं ।

उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में नई सूती मिलें

251. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सहकारी क्षेत्र में राज्यवार कितनी सूती मिलें हैं ;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और विद्युत-चालित करघा उद्योगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम हैं ;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, कानपुर एवं सुलतानपुर जिलों में नई मिलों की स्थापना करने का कोई विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की कितनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री यशोक गहलोत) : (क) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार मिलों की संख्या 120 है । (नीचे देखिए) ।

(ख) सहकारिता क्षेत्र की मिलों के अलावा हथकरघा तथा विद्युत करघा उद्योग की मांग अन्य क्षेत्रों तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों आदि द्वारा भी पूरी की जाती है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, और सुलतानपुर में नई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

30 सितम्बर, 91 की स्थिति के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों तथा फब्रिक बुनाई एककों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	सहकारिता मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
असम	1

राज्य	सहकारिता मिलों की संख्या
बिहार	3
गुजरात	5
हरियाणा	1
कर्नाटक	8
केरल	4
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	35
उडीसा	10
पंजाब	6
राजस्थान	3
तमिलनाडु	19
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	1
पांडिचेरी	1
	120

उत्तर प्रदेश को विभिन्न उपक्रमों से कोयले की आपूर्ति

252. **चौधरी हरि सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने बिजली पैदा करने वाले कारखानों के लिए भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों से कोयला प्राप्त करती है;

(ख) यदि हां, तो वह एक वर्ष में कितना कोयला लेती है;

(ग) कोयले की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) केवल वर्ष 1990-91 के लिए इस शीर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नवलेगौड़ा) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तापीय विद्युत गृह, कोल इंडिया लि० की निम्नलिखित सहायक कंपनियों से कोयला प्राप्त कर रहे हैं :-

1. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
3. नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(ख) अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों द्वारा प्राप्त किए कुल कोयले की मात्रा के संबंध में ब्यौरा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित रूप में दिया गया है :-

	(आंकड़े लाख टन में अनंतिम)
उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत गृह	59.92

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति किए गए कोयले के संबंध में दिनांक 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार देय कुल बकाया अनंतिम राशि 54210 लाख रु० थी।

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति किए गए कोयले की कुल देय बकाया अनंतिम राशि 3896 लाख रु. होने का हिसाब लगाया गया है।

Shortage of Silk Yarn

253. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the steps taken to meet the acute shortage of silk yarn to the weavers in the country;

(b) by what time this shortage will be met to make the silk yarn available; and